परिवर्तन आता है तो निधियों की आवश्यकता तथा क्षमता में भी परिवर्तन करना पड़ता है। योजना के पूंजीप्रधान मॉडल के अधीन निधियों की आवश्यकता श्रम प्रधान मॉडल से अधिक होगी। आठवीं योजना के दौरान कृषि में जोड़े गए सकल मूल्य में 3.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होने की आश है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में हुआ कुल निवेश वर्ष 1991-92 के मुल्य पर 1,48,800 करोड़ रुपये आंका गया है।

(ङ) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान कृषि में सकल पूंजी निर्माण के लिए किया गया कुल निवेश विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि में सकल पूंजी निर्माण का अनुमान

(करोड़ रू० में)

वर्ष	वर्तमान मूल्य	1980-81 का मूल्य
1990-91	11592	4594
1991-92	13390	4729
1992-93	16617	5371
1993-94	18481	5586
1944-95*	20974	5857

* त्वरित अनुमान

''कपार्ट'' द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड

966. श्री गोविन्द राम मिरी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''कपार्ट'' द्वारा सामाजिक-शैक्षणिक विकास केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) सरकार द्वारा अब तक मध्य प्रदेश के बिलासपुर और रायपुर जिलों के विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के व्यापक रूप से प्रसार-प्रचार के लिए सरकार द्वारा किन-किन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच. पटेल): (क) से (ङ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकान

967. श्री रामदेव भंडारी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत एक यूनिट मकान का खर्च कितना है;

(ग) क्या देश के सभी राज्यों में एक यूनिट मकान का खर्च एक जैसा है;

(घ) क्या एक यूनिट के खर्च को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) मैदानी एवं सुगम क्षेत्र में एक यूनिट मकान के लिए खर्च की सीमा इस समय 14,000 रुपए है, जबकि पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में यह 15,800 रुपए है। एक यूनिट मकान के खर्च में स्वच्छ शौचालय, धुंआरहित चूल्हा, ढांचा और सामान्य सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) एक यूनिट मकान के खर्च को बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

1994-95 और 1995-96 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकान

(आवासों की संख्या)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96 (31.1.1996 की स्थिति) के अनुसार
1.	आंध्र प्रदेश	57483	34659
2.	आरुणाचल प्रदेश	219	72
3.	असम	6862	19852
4.	बिहार	59216	65812
5.	गोआ	201	401
6.	गुजरात	7895	10711
7.	हरियाणा	3536	4303
8.	हिमाचल प्रदेश	853	434
9.	जम्मू कश्मीर	1697	2397
10.	कर्नाटक	13831	18203
11.	केरल	3891	14664
12.	मध्य प्रदेश	18967	75147
13.	महाराष्ट्र	22812	14069
14.	मणिपुर	171	512
15.	मेघालय	241	83
16.	मिजोरम	368	424
17.	नागालैंड	895	470
18.	उड़ीसा	13297	19316
19.	पंजाब	3849	1121
20.	राजस्थान	28934	32250
21.	सिक्किम	108	875
22.	तमिल नाडु	33176	36882
23.	त्रिपुरा	567	45
24.	उत्तर प्रदेश	47555	123472
25.	पश्चिम बंगाल	15526	16840
26.	अंडमान निकोबार	21	60
27.	दादर नगर हवेली	59	13
28.	दमन व द्वीव	45	4
29.	लक्ष द्वीव	0	4
30.	पांडिचेरी	0	18
	कुल:	372275	493106

Concessional rates of custom duty

968. *SHRI NAGMANI:* Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

(a) the names of drug intermediate where concessional rates of custom duty have been levied viz-a-viz other drug intermediates for production of basic drugs for which there is the foreign exchange outflow; and

(b) what are the imbalance and intermediated profit has been occurred to the industries year-wise for the last two years?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) The names of raw materials and drug intermediates on which customs duty concessions have been granted by the Finance Ministry are given in the custom Notifications No. 15/95 dated 16.3.95 and 16/95 dated 16.3.95.

(b) This information is not monitored by this Ministry.

Expansion of Copper Complexes

969. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal for the expansion and modernisation of some of the copper complexes in the country;

(b) if so, which copper mines or copper complexes are proposed to be expanded during Eighth and Ninth Five Year Plan;

(c) the fund earmarked for the expansion of these copper mines; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) to (d) Yes, Sir. Hindustan Copper Limited (HCL) has formulated the following expansion/modernisation plans; (i) expansion of Khetri Smelter and Refinery Plant from a capacity of 31000 TPA to 100000 TPA (ii) opening of Banwas copper mine (iii) expansion of Rakha copper mine from 1000 TPD to 2000 TPD (iv) expansion of Malanjkhand open pit mine and concentrator from 2 Million Tonnes to 2.3 Million Tonnes per annum and (v) modernisation of Indian Copper Complex and Khetri Copper Complex concentrators.

The Company is also working on the proposal for opening of underground mines at Chapri-Sidheswar and Malanjkhand copper deposits.